

मुकदमों का विवरण

बालवीर सिंह बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य (2015 की आपराधिक अपील संख्या 301) 06 अक्टूबर, 2023

[जे. बी. पारदीवाला और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें अपीलार्थी-पति को दंडनीय यू/एस हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया था।³⁰² दंडनीय यू/एस के साथ आई. पी. सी.⁴⁹⁸ आई. पी. सी. की ए और अपीलार्थी-सास दंडनीय यू/एस के दोषी हैं।⁴⁹⁸ आई. पी. सी. का ए आर/डब्ल्यू³⁴ आई. पी. सी. की, क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

दंड संहिता, **1860 -s.302,s.498A**-अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित की मौत जहर के कारण हुई-मृत्यु के समय केवल उसका अपीलकर्ता-पति मौजूद था-मृतक के विसरा की जांच में जहर पाया गया-अपीलकर्ता-पति ने पीड़ित के परिवार को उसकी मृत्यु के बाद सूचित नहीं किया था-इससे पहले, पीड़ित-मृत ने अपने परिवार को पत्र लिखकर अपने अपीलकर्ता-पति और दहेज के लिए अपीलकर्ता-सास से उत्पीड़न के बारे में सूचित किया था:

आयोजित किया गया: मौत का कारण विषाक्तता था-विसरा में पाया गया जहर एल्यूमीनियम फॉस्फाइड था, जिसका उपयोग कीड़ों और कृन्तकों को नियंत्रित करने के लिए एक धुंधला पदार्थ के रूप में किया जाता है-दोषियों का बचाव यह कहने के लिए कि विसरा में एल्यूमीनियम फॉस्फाइड की उपस्थिति उन दवाओं के कारण हो सकती है जो मृतक अपनी हृदय की बीमारी के लिए लेता था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है-अपीलकर्ता-पति के नेतृत्व में कोई सबूत नहीं है कि वह पीड़ित को दिल्ली के अस्पताल ले गया था-दोषी-पति का संदिग्ध आचरण परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में सूचित नहीं करने के लिए-हाथ में मामले में यह स्थापित किया गया है या अदालत की संतुष्टि के लिए साबित हुआ है कि मृतक अपने पति के साथ था यानी अपीलकर्ता।

815 816

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

उस समय जब उसके स्वास्थ्य के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी और इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में केवल अपीलकर्ता-दोषी को ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ था जब तक कि वह उसके साथ नहीं थी-अपीलकर्ता-दोषी (पति) ने किसी भी तरह से यह नहीं बताया कि वास्तव में उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था, विशेष रूप से जब यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता-दोषी अपनी पत्नी के साथ था, अर्थात् मृत-हालाँकि, अपीलकर्ता-दोषी ने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि जैसे ही मृतक बीमार पड़ गया, वह उसे तुरंत दिल्ली के अस्पताल ले गया-यदि यह उसका मामला है, कि उसकी पत्नी को अस्पताल में लाए जाने पर मृत घोषित कर दिया गया था, तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि अस्पताल के अधिकारियों ने अपील करने वाले को अनुमति दी थी।¹⁰⁶ साक्ष्य अधिनियम और अभियुक्त पति पर यह समझाने का भार डाला जाए कि उसकी पत्नी की मृत्यु की तारीख को वास्तव में क्या हुआ था-धारा 106 आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त पर कोई बोझ नहीं डालती है, लेकिन यह कि, जहां अभियुक्त उन तथ्यों पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में होने चाहिए, और जो उसकी बेगुनाही के साथ संगत परिकल्पना के किसी भी सिद्धांत का समर्थन कर सकते हैं, न्यायालय देवनंदन मिश्रा के मार्ग के सिद्धांत के अनुरूप कोई स्पष्टीकरण देने में उसकी विफलता पर भी विचार कर सकता है-अदालतें ऐसे मामलों को अधिक यथार्थवादी तरीके से निपटेंगी और अपराधियों को प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं, निष्पक्ष जांच या साक्ष्य में मामूली कमियों के कारण भागने की अनुमति नहीं देंगी-परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं।[पारस 29,52,53,56,61 और 62]

साक्ष्य अधिनियम, **1872 -s.106**-प्रयोज्यता-"विशेष रूप से" शब्द का अर्थ:

आयोजित किया गया: साक्ष्य अधिनियम के <आई. डी. 1 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान के भीतर होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है-"विशेष रूप से" शब्द का अर्थ है ऐसे तथ्य जो

अभियुक्त के ज्ञान के भीतर प्रमुख रूप से या असाधारण रूप से होते हैं-सामान्य नियम जो आपराधिक मुकदमों पर लागू होता है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती है, किसी भी तरह से एस में सन्निहित तथ्यों के नियम द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है।**106** साक्ष्य अधिनियम -साक्ष्य अधिनियम का **s.106** एस के लिए एक अपवाद है।**101** साक्ष्य अधिनियम। [पैरा 34]

साक्ष्य अधिनियम, **1872 -s.106** अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है:

817

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य **818**

आयोजित किया गया:धारा **106** को अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों का साक्ष्य पेश करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता को पूरा करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है-इस धारा का उपयोग दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष ने अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है-यह अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है कि अपराध किया गया था, भले ही यह विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में एक मामला हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का बोझ नहीं डालता है कि कोई अपराध नहीं किया गया था।[पैरा 42]

साक्ष्य अधिनियम, **1872 -s.106**-सबूत के बोझ और सबूत के साथ आगे बढ़ने के बोझ के बीच अंतर मौजूद है:

आयोजित किया गया:आम तौर पर, किसी मुद्दे की नींव के रूप में स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक किसी भी संबंधात्मक प्रस्ताव पर सबूत का बोझ नहीं बदलता है, लेकिन साक्ष्य का बोझ या स्पष्टीकरण का बोझ गवाही के अनुसार एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो सकता है-इस प्रकार, यदि अभियोजन पक्ष के पास साक्ष्य है जो अदालत द्वारा विश्वास किए जाने पर उन्हें उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध के बारे में आश्वस्त करेगा, तो आरोपी ऐसी स्थिति में है जहां उसे जवाबी सबूत के साथ आगे बढ़ना चाहिए यदि उसके पास ऐसा सबूत है-जब तथ्य विशेष रूप से आरोपी के ज्ञान के भीतर हैं, तो ऐसे तथ्यों का सबूत पेश करने का बोझ उस पर है, चाहे प्रस्ताव एक संबंधात्मक या नकारात्मक हो-उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही प्रथम दृष्टया मामला हो।[पैरा 46]

साक्ष्य अधिनियम, **1872 -s.106-s** के संदर्भ में "प्रथम दृष्टया"।**106:**

आयोजित किया गया:साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष को उन तथ्यों को साबित करने में सफल कहा जा सकता है जिनसे मृत्यु के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।[पैरा 48]

शहरों और अन्य
संदर्भों की सूची

शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य ए. आई. आर. **1956** एस. सी. **404**:[**1956**] एस. सी. आर. **199**; नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य (2021) **10** एस. सी. सी. **725**; तुलसीराम

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[**2023**] **12** एस सी आर।

सहदु सूर्यवंशी और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) **10** एस. सी. सी. **373**:[**2012**] **7** एस. सी. आर. **1083**;
त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2006) **10** एससीसी **681**:[**2006**] **7** पूरक।एससीआर **156**; राज्य डब्ल्यू. बी. बनाममीर मोहम्मद उमर और अन्य
(2000) **8** एस. सी. सी. **382**:[**2000**] **2** पूरक।एससीआर

712; राम गुलाम चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य (2001) 8 एस. सी. सी. 311:[2001] 3 पूरक।एस. सी. आर. 279; देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 801; कालू उर्फ लक्ष्मीनारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(2019) 10 एससीसी 211:[2019] 14 एस. सी. आर. 327; सावल दास बनाम बिहार राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 193:[1974] 3 एस. सी. आर. 74-पर निर्भर।

लेलैंड बनाम राज्य 343 यू. एस. 790 = 96 एल. एड 1302; राफ़ एल बनाम यू. एस. 271 यू. एस. 294 = 70 एल. एड. 1054-संदर्भित।

स्मिथ बनाम आर. 1918 ए. आई. आर. पागल। 111-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2015 की आपराधिक अपील संख्या 301।

2013 के सी. आर. एल. ए. No.273 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.03.2014 के निर्णय और आदेश से।

सह

2014 की आपराधिक अपील संख्या 2430।

रूप:

मनीषा भंडारी, ओंकार श्रीवास्तव, दिव्यदीप चतुर्वेदी, आयुष जैन, ध्रुव चंद्र, शाश्वत सिद्धांत, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जतिंदर कुमार भाटिया, कृष्णम मिश्रा, परम कुमार मिश्रा, राजीव कुमार दुबे, कमलेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. बी. पारदीवाला, न्या

1. चूँकि दोनों शीर्षांकित अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा दो 819 की दो आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए पारित एक सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं।

बालवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 820

अभियुक्त व्यक्तियों पर एक सत्र मामले में मुकदमा चलाया गया, जिन्हें समान रूप से सुना गया था और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. ये अपीलों दो दोषियों के कहने पर की गई हैं और क्रमशः 2013 की आपराधिक अपील संख्या 273 और 2013 की आपराधिक अपील संख्या 274 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और इस तरह 2008 की सत्र सुनवाई संख्या 48 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कोटद्वार, गढ़वाल द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को स्वीकार कर लिया।

रोग होने का कारण

3. मृतक सुधा का विवाह बलवीर सिंह से हुआ था।बलवीर सिंह के साथ मृतक की शादी 12.12.1997 पर संपन्न हुई।विवाह में एक पुत्र का जन्म हुआ।मृतक के पिता, वीरेंद्र सिंह (पीडब्लू1) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोटद्वार, गढ़वाल की अदालत में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी बेटी की मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोटद्वार, गढ़वाल ने निम्नलिखित आदेश दिनांक 04.06.2006 पारित किया:

“ आदेश दें

04.06.2006

आवेदक विरेन्द्र सिंह ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के लिए आदेश पारित करने के लिए धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन किया था, जिसमें आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदक सुधा की बेटी की शादी 12.12.1997 को गांव रतनपुर, कुंभचौ, हलका-सनेह, कोटद्वार, गढ़वाल के निवासी स्वर्गीय महावीर सिंह के बेटे बलवीर सिंह के साथ हुई थी। विवाह समारोह के कुछ समय बाद बलवीर सिंह और श्रीमती. माहेश्वरी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

बलवीर सिंह की देवी माँ ने मिलकर मेरी बेटी को अलग-अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया और रुपये की मांग करना शुरू कर दिया। दहेज में एक लाख नकद। आवेदक की बेटी ने पत्रों के माध्यम से आवेदक को इसके बारे में सूचित किया। बलवीर सिंह दिल्ली के एक निजी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं और वह दवाओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आवेदक के अनुसार, बलवीर सिंह अपनी बेटी की हत्या करने से पहले नकली पर्ची की व्यवस्था करने में कामयाब रहा जो उसने अपने पास रखी थी। अपनी बेटी की अनिच्छा के बावजूद, आई. डी. 1 पर बलवीर ने अपने बेटे को कोटद्वार में छोड़ दिया और मेरी बेटी सुधा को जबरन मंगोलपुरी, दिल्ली ले गया, जो स्वस्थ स्थिति में थी। जाने से पहले, आवेदक की बेटी ने दिल्ली जाने के लिए अपनी अनिच्छा के बारे में अपने चाचा को टेलीफोन पर अपनी इच्छा व्यक्त की। रात के लगभग 1:30 बजे आवेदक के छोटे भाई हरेंद्र सिंह को दिल्ली से फोन पर जानकारी मिली कि उनकी बेटी सुधा अचानक मंगोलपुरी में अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गई है। बलवीर सिंह ने यह जानकारी परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं दी, बल्कि किसी पड़ोसी ने यह जानकारी हरेंद्र सिंह के छोटे भाई शिवचरण को दी, जो दिल्ली में रहता है। शिवचरण रात में ही मंगोलपुरी गए, जहाँ उन्हें पता चला कि उस रात उनकी तबीयत ठीक है और मृतक की मृत्यु के बाद बलवीर सिंह बिना किसी को जानकारी दिए निजी एम्बुलेंस से उनके शव को रतनपुर, कोटद्वार स्थित अपने घर ले गए। जब आवेदक को इस तथ्य के बारे में पता चला तो उसने कोटद्वार पुलिस स्टेशन को सूचित किया। आवेदक की बेटी के गले पर लाल रंग की चोट के निशान स्पष्ट थे, जिसके कारण पुलिस ने जांच शुरू की और शव के पोस्टमॉर्टम की व्यवस्था की।

आवेदक के नेतृत्व में आवेदन पर पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगने पर, पुलिस स्टेशन ने प्रस्तुत किया है कि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदक द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर पुलिस स्टेशन में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं है।

अपने आवेदन के समर्थन में आवेदक द्वारा दायर दस्तावेजों के आधार पर, प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण आवश्यक प्रतीत होता है।

821

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 822

इसलिए, एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन कोटद्वार को आदेश दिया जाता है कि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदक के नेतृत्व में आवेदन के आलोक में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और जांच की जाए।

ह /-

न्यायिक मजिस्ट्रेट "

4. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट कोटद्वार पुलिस स्टेशन में आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242, 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1961') की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है:

“महोदय, आवेदनकर्ता स्वर्गीय मोहन सिंह के पुत्र, गाँव मवासा, पट्टी-अजमेर पाल, तहसील कोटद्वार गढ़वाल के निवासी, विरेन्द्र सिंह सम्मानपूर्वक निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1. कि मेरी बेटी सुधा की शादी आई. डी. 1 को गांव रतनपुर, कुंभचौर, हलका-सनेह, कोटद्वार, गढ़वाल के निवासी स्वर्गीय महावीर सिंह के बेटे बलवीर सिंह के साथ, कोटद्वार पुलिस स्टेशन के उत्तर झंडीचौर में स्थित मेरे छोटे भाई के घर से हुई थी और शादी से उनके एक बेटे का जन्म हुआ था।

2. वह शादी के कुछ समय बाद, बलवीर सिंह और श्रीमती। बलवीर सिंह की मां माहेश्वरी देवी ने उसके साथ मिलकर मेरी बेटी को अलग-अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज में एक लाख रुपये नकद की मांग की। श्रीमती. माहेश्वरी देवी को पेंशन मिल रही है और उनके पास भू-संपत्ति भी है। बलवीर सिंह एक लालची व्यक्ति है और अपनी माँ की पेंशन के लालच में, वह मेरी बेटी को परेशान कर रहा है और उसे पीट रहा है, उसे खाना नहीं दे रहा है, और गाँव की महिलाएं किसी तरह इन लोगों से छिपकर उसे खाना देती हैं। मेरी बेटी ने इस तथ्य के बारे में शिकायत करते हुए हमें पत्र लिखा। जब बलवीर सिंह और उनकी मां को इन पत्रों के बारे में पता चला, तो उन्होंने मेरी बेटी पर उक्त पत्रों को वापस मांगने के लिए दबाव डाला और हमने तदनुसार उन पत्रों को वापस कर दिया, लेकिन हमारे द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया 20.05.04 का पत्र हमारे पास ही रहा। इसमें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

पत्र में मेरी बेटी ने भी अपनी शिकायतों और उत्पीड़न का सामना किया है।

3. इस घटना की जानकारी मिलने पर मैं, मेरे कुछ रिश्तेदार, पंच और प्रधान रतनपुर वहां गए और उन्होंने बलवीर सिंह और उनकी मां को इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं होने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि भविष्य में मेरी बेटी वहां ठीक से रह सके और मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन, माहेश्वरी देवी और बलवीर सिंह मेरी बेटी सुधा को खत्म करने की साजिश रचते रहे। एक बार उन्होंने मेरी बेटी को भी जहर पिलाया था लेकिन मेरी बेटी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी।

4. कि बलवीर सिंह दिल्ली के एक निजी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं और वह दवाओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। मेरी बेटी की हत्या करने से पहले, वह नकली और जाली पर्ची की व्यवस्था करने में कामयाब रहा, जो पुलिस को भी दिखाई गई है, और इन पर्ची और दवाओं के बारे में जांच की आवश्यकता है। 09.05.07 पर मेरी बेटी की अनिच्छा के बावजूद बलवीर ने अपने बेटे को स्वस्थ हालत में कोटद्वार में छोड़ दिया और मेरी बेटी सुधा को जबरन दिल्ली के मंगोलपुरी में ले गया। जाने से पहले, मेरी बेटी ने टेलीफोन पर मेरे छोटे भाई हरेंद्र से दिल्ली जाने की अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

5. कि रात के लगभग 1:30 बजे मेरे छोटे भाई हरेंद्र सिंह को दिल्ली से फोन पर जानकारी मिली कि मेरी बेटी सुधा अचानक मंगोलपुरी में अपने स्वर्गीय निवास के लिए चली गई है। बलवीर सिंह ने यह जानकारी हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दी, बल्कि किसी पड़ोसी ने यह जानकारी हरेंद्र सिंह के छोटे भाई शिवचरण को दी, जो दिल्ली में रहता है। शिवचरण उस रात मंगोलपुरी गए, जहाँ उन्हें पता चला कि उस रात मेरी बेटी की तबीयत ठीक है और मेरी बेटी की मृत्यु के बाद बलवीर सिंह बिना किसी को जानकारी दिए निजी एम्बुलेंस से उसके शव को रतनपुर, कोटद्वार स्थित अपने घर ले गए। जब हमें इस तथ्य के बारे में पता चला तो हमने पुलिस स्टेशन कोटद्वार की पुलिस को सूचित किया लेकिन हम उस समय सभी विवरण प्रदान नहीं कर सके। चूंकि मेरी बेटी की गर्दन पर लाल चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, इसलिए पुलिस ने जांच शुरू की और उसके शव के पोस्टमार्टम की व्यवस्था की। महोदय, मेरे पास यह मानने का कारण है कि उक्त माहेश्वरी देवी और उनके बेटे बलवीर सिंह ने 823 लोगों की हत्या की है।

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 824

मेरी बेटी ने साजिश रची है और अपने छोटे बच्चे को भी उनके पक्ष में उकसाया है।

6. कि उसकी सास और उसके पति बलवीर सिंह ने मेरी बेटी का अमानवीय उत्पीड़न किया जो एक जघन्य अपराध है। उनके पत्रों की फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न की जा रही हैं। मैंने पुलिस स्टेशन और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन अब तक कोई पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि कृपया पुलिस स्टेशन कोटद्वार की पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करने का आदेश दें।

तारीख:02.06.07.आवेदक-एस. डी./- स्वर्गीय मोहन सिंह के पुत्र विरेंद्र सिंह, गाँव मवासा, पट्टी-अजमेर पल्ला, तहसील-कोटद्वार, जिला-पुरी गढ़वाल के निवासी।

ध्यान दें:मैं, उच्च न्यायालय 14 कबूल सिंह प्रजापति एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि औपचारिक रिपोर्ट की प्रति शब्द-दर-शब्द दर्ज की गई है जो स्पष्ट रूप से सुपाठ्य है।ह /-

एच. सी. 14 कबूल सिंह

पुलिस थाना कोटद्वार

तारीख:09.06.07”

5. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद जांच की गई।दिल्ली से कोटद्वार लाए जाने पर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।स्वतंत्र पंच गवाहों की उपस्थिति में पूछताछ पंचनामा तैयार किया गया था।जांच अधिकारी द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पोस्टमॉर्टम के दौरान एकत्र किए गए विसरा को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था।यहां दोनों अपीलार्थियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

6. जाँच के समापन पर, ऊपर गिने गए अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।निचली अदालत द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से बनाए गए आरोप के लिए, अपीलकर्ताओं ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।7. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व किया:

क. पीडब्लू1 विरेंद्र सिंह (मृतक के पिता)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

ख. पीडब्लू2 डॉ. इंद्र सिंह सामंत, सरकार। अस्पताल (वह डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया)

ग. पीडब्लू 3 हरेंद्र सिंह (मृतक के चाचा) डी।पी. डब्ल्यू. 4. बलबीर सिंह (मृतक के एक अन्य चाचा) ई.पीडब्लू 5 एम. एम. एस. बिष्ट (वरिष्ठ उप निरीक्षक)

च. पीडब्लू6 बलदेव सिंह (जाँच कार्यवाही के पंच गवाह) एच.पीडब्लू 7 कबूल सिंह (हेड कांस्टेबल)

8. अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य का भी नेतृत्व किया जो इस प्रकार है:ए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Exh.Ka-4

ख. पूछताछ रिपोर्ट Exh। केए-5

ग. मृतक द्वारा अपने पिता को लिखे गए दो पत्र अर्थात पीडब्लू1 एक्श। केए-1 और केए-2।

9. इसमें अपीलकर्ताओं ने बचाव पक्ष के गवाह (डी. डब्ल्यू.-1) के रूप में मृतक के बेटे शिवम रावत से पूछताछ की। अपीलकर्ताओं ने बचाव पक्ष के गवाह (डी. डब्ल्यू.-2) के रूप में मृतक के चचेरे भाई अनूप सिंह से भी पूछताछ की।

10. मौखिक साक्ष्य के समापन पर, दोनों अपीलार्थियों का आगे का बयान निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया था।निचली अदालत ने दोषी बलवीर सिंह से दो विशिष्ट प्रश्न पूछे और दोनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार था:

“प्रश्न संख्या 14:- क्या आपको कुछ और कहना है?

जवाब:- मैं निर्दोष हूँ।शिकायतकर्ता ने झूठा मामला दर्ज कराया है।प्रश्न संख्या 15:- मृतक के विसरा की जांच में जहर पाया गया है।इस संबंध में आपका क्या कहना है?

जवाब:- मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि जहर कैसे मिला, लेकिन मृतक हृदय रोगी था और दवाओं का सेवन करता था।”

11. मृतक की सास ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने आगे के बयान में कहा कि वह निर्दोष थी और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था।

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 826

12. निचली अदालत ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पर पति को आई. पी. सी. की धारा 242 के तहत दंडनीय हत्या और आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दंडनीय उत्पीड़न का भी दोषी ठहराया। निचली अदालत ने पति को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10, 000/- सास, अर्थात् माहेश्वरी देवी को निचली अदालत ने हत्या के अपराध से बरी कर दिया, हालाँकि, वह निचली अदालत द्वारा आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराई गई और उसे ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

13. निचली अदालत ने अपीलार्थियों को ऊपर बताए गए अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए निम्नलिखित तथ्य दर्ज किए:

"21. मृतक की मौत जहर से हुई। हालाँकि अभियोजन पक्ष स्पष्ट सबूत नहीं ला सका कि पीड़ित को आरोपी द्वारा जहर दिया गया था, लेकिन उत्पीड़न के संबंध में पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 ने सबूत पेश किए हैं। यह प्रदर्शनी ए 1 और प्रदर्शनी ए 2 द्वारा भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा, उसकी मृत्यु के बाद विसरा रिपोर्ट में जहर पाया गया। हालाँकि, बचाव पक्ष द्वारा इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि यह मृतक के शरीर में कैसे घुस गया। अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था और उससे स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि मृतक की आंत जांच रिपोर्ट में जहर पाया गया था, आपको इसके बारे में क्या कहना है? इस बारे में आरोपी बलवीर सिंह ने कहा कि "मुझे नहीं पता कि यह कैसे पाया गया, लेकिन मृतक हृदय रोगी था और दवा ले रहा था।" इस संबंध में, बचाव पक्ष ने डी. डब्ल्यू.-1 की जांच की जो मृतक का बेटा है और जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि "मेरी माँ का दिल्ली में इलाज चल रहा था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई।" उन्होंने आगे कहा, "मेरी दादी और पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।" वह एक बाल गवाह है। इस गवाह ने बताया कि मृतक की मृत्यु उपचार के दौरान हुई थी, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि उसका इलाज कहाँ चल रहा था, या उसकी मृत्यु कैसे हुई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मृतक एक हृदय रोगी था और जिसके कारण मृत्यु हुई लेकिन विसरा रिपोर्ट द्वारा इस तर्क को नकार दिया गया है। बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए डी. डब्ल्यू.-2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि "आरोपी मृतक का दिल्ली में लगातार इलाज करा रहा था। मृत सुधा अपनी बीमारी के कारण व्यथित थी। आरोपी सुधा की देखभाल करता था। बलवीर सिंह और उसकी माँ ने उसे परेशान नहीं किया, और यह कि उसने कुछ किया होगा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अपनी बीमारी के कारण खुद के लिए "। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस गवाह ने अपने साक्ष्य को नए तथ्यों पर आधारित किया है। प्रतिपरीक्षा के दौरान, बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह से पूछताछ के दौरान, ऐसे मामले के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया था कि क्या मृतक अपनी बीमारी से पहले या अपनी बीमारी के कारण व्यथित थी। डी. डब्ल्यू.-1, जो मृतक का बेटा है और जिस पर बचाव पक्ष ने जोर दिया है, ने मृतक की बीमारी के कारण व्यथित होने के बारे में कुछ नहीं कहा है। डी. डब्ल्यू.-1 ने केवल यह कहा है कि मृत्यु उपचार के दौरान हुई है, जबकि डी. डब्ल्यू.-2 ने अपने साक्ष्य को नए तथ्यों पर आधारित किया है जो बचाव के तथ्यों से सहमत नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि उपचार एस्कोर्ट्स अस्पताल में दिया गया था। इस संबंध में बचाव पक्ष ने पीडब्लू-1 से सवाल किया है कि वर्ष 2006 में आरोपी ने एस्कोर्ट्स अस्पताल में रुपये के बिल का भुगतान किया था जिसका उसने खंडन किया था। इस संबंध में बचाव पक्ष ने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। मैंने उन दस्तावेजों की जांच की है। हालाँकि बचाव पक्ष ने उन दस्तावेजों को साबित नहीं किया है, लेकिन पृष्ठ संख्या 48 ए/2 में रुपये का एक दस्तावेज मौजूद है जो डॉ. नितीश चंद्र द्वारा दिया गया था, लेकिन कहा गया है कि दस्तावेज भुगतान का बिल नहीं है, बल्कि यह पूर्ण जांच और संचालन के लिए आवश्यक एक अनुमान है, क्योंकि दस्तावेज में लिखा है कि-'एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड के पक्ष में केस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रवेश के समय अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। नई दिल्ली में देय।' दस्तावेज को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त और अन्य लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया। इसके अलावा रुपये 3,82,500-के भुगतान के लिए फाइल में कोई दस्तावेज नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है।

22. इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-4 से जिरह की गई। बचाव पक्ष द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कहा है, "यह सच है कि जाँच रिपोर्ट में मृतक के पति ने कहा कि बेटे के जन्म के बाद मेरी पत्नी बीमार रहती थी। अक्सर, उसे बेहोशी की घटनाएँ होती थीं। 13 मई 2007 की रात 10 बजे:00 अपराह्न, उसे दौरा पड़ा और वह होश में नहीं आई। मैं उसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस गवाह ने अपनी जिरह में बयान दिया कि मृतक

की मृत्यु संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में हुई, जिसके बारे में कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था। हालाँकि इस गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि यह बात उसे बलवीर सिंह ने बताई थी। यह गवाह बचाव का समर्थन कर रहा है, लेकिन यह गवाह का बयान 827 के विपरीत है।

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 828

फाइले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य। यदि आई. डी. 1 पर हमला होने के बाद आरोपी ने मृतक को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया, तो इस बारे में कोई दस्तावेज नहीं हैं और बचाव पक्ष ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है।

23. बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि मृतक सुधा की मृत्यु 13.5.2007 पर हुई थी। 13.5.2007 पर उसका अंतिम संस्कार किया गया और शिकायतकर्ता ने 2.6.2007 पर धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज कराया। आवेदन बहुत देर से किया गया था और यह देरी नहीं हुई है। समझाया। बचाव के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। पीड़ित की मृत्यु 13.5.2007 पर हुई और कहा जाता है कि 13.5.2007 पर उसका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन मृत्यु की खबर मिलने पर अभियोजन पक्ष के गवाह ने तुरंत अपने संदेह को सामने रखा। जाँच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मृतक सुधा की मृत्यु संदिग्ध है, और पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। उपरोक्त जाँच रिपोर्ट में पीडब्ल्यू-1 गवाहों में से एक है, वह मृतक का पिता भी है। और पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में जाँच की गई। साक्ष्य के दौरान गवाह ने कहा है कि "बलवीर दिल्ली के मंगोलपुरी में रहता है। शिवचरण को पड़ोसियों ने सूचित किया कि सुधा की मृत्यु हो गई है और वे शव को रतनपुर ले आए। अगले दिन मैं कोर्टद्वारा आया। मैंने यह जानकारी पुलिस स्टेशन को दी। फिर पुलिस और मैं रतनपुर आए। वहाँ पुलिस ने जाँच रिपोर्ट तैयार की। जाँच रिपोर्ट में मुझे भी गवाह बनाया गया था। जैसे ही गवाह को यह जानकारी मिली, उसने घटना पर संदेह जताया। थाने को सूचना दी गई। इस गवाह ने आगे कहा, "मैंने उसकी मौत की जाँच के लिए पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा था। इस संबंध में मैंने एस. डी. एम., कोर्टद्वारा को लिखित शिकायत की। इस गवाह ने आगे कहा, "फिर, मैंने अपने वकील की मदद से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक याचिका का नेतृत्व किया, जिस पर अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया।" घटना की जानकारी मिलने पर इस गवाह ने तुरंत संदेह जताया और पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा। 14.5.2007 पर मृतक की मौत की जाँच के लिए पुलिस स्टेशन को एक आवेदन लिखा गया था। पुलिस ने जाँच रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया। इस स्थिति में, बचाव पक्ष इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि इस गवाह ने पुलिस स्टेशन और एस. डी. एम. को सूचित किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

24. विसरा रिपोर्ट में एफएसएल ने जहर का पता लगाया है, ऐसी स्थिति में आरोपी पर यह साबित करने का बोझ था कि क्या मृतक ने खुद जहर खाया था और क्या मृतक मानसिक तनाव में था जिसके कारण उसने जहर खाया होगा, लेकिन बचाव पक्ष ने पूरे मुकदमे के दौरान इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अंत में डी. डब्ल्यू.-2 ने यह सबूत प्रस्तुत किया कि मृतक अपनी बीमारी के कारण व्यथित थी, लेकिन पूरे मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मृतक हृदय रोगी था और उसका इलाज चल रहा था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि मृतक दवा ले रहा था और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण दवा स्वाभाविक रूप से जहर में बदल सकती है, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया था, और कोई चिकित्सा राय नहीं ली गई थी कि मृतक ऐसी प्रकृति की दवा ले रहा था जो रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण शरीर में जहर में बदल सकती है। चूंकि यह बचाव पक्ष द्वारा उठाया गया था, ऐसी स्थिति में इसे साबित करने का बोझ उन पर था, लेकिन इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (जी) के अनुसार-वह साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जा सकता है और जो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यदि प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे रोकने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिकूल होगा। 25. प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण दवा मृतक के शरीर में जहर में बदल सकती है, इसलिए सबूत का बोझ बचाव पक्ष पर था, लेकिन इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में धारा 114 (जी) के तहत यह मान लेना महत्वपूर्ण है कि यदि आरोपी द्वारा कोई सबूत पेश किया गया होता तो वह उसके खिलाफ होता, जिसके कारण बचाव पक्ष द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। लेकिन मृतक की मौत दिल्ली में हुई। आरोपी बलवीर सिंह शव को दिल्ली से कोर्टद्वारा ले आया। पीडब्ल्यू-1 ने अपने जाँच-प्रभारी ने कहा है कि "यह सच है कि मेरी बेटी दिल्ली में आरोपी के साथ रह रही थी।" पीडब्ल्यू-1 द्वारा दिए गए बयान के आधार पर, मृतक की मृत्यु दिल्ली में हुई, जहाँ वह आरोपी बलवीर सिंह के साथ रह रही थी। विसरा रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मौत जहर से हुई। मौत के समय केवल आरोपी

बलवीर सिंह मौजूद था। आरोपी माहेश्वरी देवी दिल्ली में नहीं थी। चूंकि, मृतक की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, इसलिए ऐसी स्थिति में माहेश्वरी देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 30 के तहत आरोप नहीं पाया जाता है।

26. जहां तक दहेज का सवाल है, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 ने इस मामले में आरोपी बलवीर सिंह के खिलाफ 829 सबूत पेश किए हैं।

बलवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 830

और श्रीमती माहेश्वरी देवी कि वे दहेज की मांग कर रहे हैं। यह तथ्य दस्तावेज पत्रों द्वारा भी साबित होता है जो ए-1 को प्रदर्शित करते हैं और ए-2 को प्रदर्शित करते हैं। आरोपी बलवीर सिंह और श्रीमती माहेश्वरी देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत आरोप संदेह से परे साबित होता है।

27. उपरोक्त दलीलों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी बलवीर सिंह और माहेश्वरी देवी ने दहेज के लिए मृतक के साथ दुर्यवहार और उत्पीड़न किया और मृतक से 1 लाख रुपये की मांग की। इसलिए आरोपी बलवीर सिंह और माहेश्वरी देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए/34 के तहत दोषी ठहराया जाना है। क्योंकि इस घटना में मृतक की मृत्यु हो गई है और यह सबूत सामने आया है कि मृतक आरोपी बलवीर सिंह के साथ दिल्ली में रह रहा था, इसलिए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत आरोप साबित होता है और उसे उक्त आरोप के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मृतक की मृत्यु के समय आरोपी श्रीमती माहेश्वरी देवी बलवीर सिंह के साथ दिल्ली में थीं और मृतक की मृत्यु में माहेश्वरी देवी की कोई भूमिका साबित नहीं हुई है, इसलिए श्रीमती माहेश्वरी देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 305 के तहत कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और इसलिए, उन्हें उपरोक्त आरोप से मुक्त किया जाना चाहिए।"

14. निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और दोषसिद्धि के आदेश से असंतुष्ट अपीलार्थी उच्च न्यायालय में अपील करने गए। उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और इस तरह निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा:

"3. आरोप-पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि तत्काल मामले में मौत जहर देने से हुई थी। जैसे ही मौत की सूचना मिली, पीडब्लू-1 ने शव को देखते हुए जांच के लिए जोर दिया और ऐसा ही किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने मौत के कारण पर संदेह व्यक्त किया और पोस्टमार्टम की मांग की। तदनुसार, पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मौत का कारण नहीं बता सके। तदनुसार, उन्होंने विश्लेषण के उद्देश्य से मृतक के हृदय और विसरा के एक हिस्से को संरक्षित किया। विसरा को विश्लेषण और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा के लिए भेजा गया था, जिसे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

उसी को भेजा गया था, बताया गया था कि उसी में "एल्यूमीनियम फॉस्फाइड" के रूप में जाना जाने वाला जहर था। ये सभी तथ्य आरोप पत्र में थे। आरोप पत्र के अनुसार, मौत दिल्ली में हुई थी, जब पीड़िता के साथ अकेले ए 1 मौजूद था। ए 1 ने ही पीड़ित के शव को रतनपुरी, कोटद्वार लाया था। ए 1 का यह तर्क नहीं था कि पीड़ित की किसी भी समय आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थी या उसे संदेह था कि पीड़ित ने आत्महत्या की थी। यह ए 1 का तर्क था, जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह की प्रवृत्ति से स्पष्ट है, और विशेष रूप से, अभियोजन पक्ष के गवाहों को दिए गए सुझावों से कि पीड़ित हृदय रोग से पीड़ित था, इसके लिए मामले में लगातार उपचार और दवा देने की आवश्यकता थी। यह सुझाव दिया गया था कि इस तरह की दवा, उपरोक्त जहर में बदल गई। कि ए 1 की ओर से एक दावा होने के कारण, यह वही था, जिसे पर्याप्त सबूत देकर इसे स्थापित करने की आवश्यकता थी, जो वह बुरी तरह विफल रहा। एक मृत व्यक्ति, जिसकी मृत्यु का कारण जहर था, तदनुसार, ए 1 की गोद में पाया गया। ए 1 को इसके बारे में विशेष ज्ञान था। वह इसके संबंध में कुछ भी खुलासा करने में विफल रहे। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (जी) के तहत ए 1 के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है। हम सोचते हैं कि नीचे दिया गया न्यायालय मामले की पृष्ठभूमि में ऐसा निष्कर्ष निकालने का हकदार था जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

4. तदनुसार, हम हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं समझते हैं। अपील खारिज कर दी जाती है। नीचे दिए गए न्यायालय के निर्णय को लागू किया गया है। बचाव पक्ष के लिए गवाह के रूप में आवेदक की जांच करने के लिए दायर आवेदन (2013 का सी. आर. एम. ए. सं. 1744) को दबाया नहीं गया है। वही खारिज कर दिया जाता है। ए 1 जेल में है। वह नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दी गई सजा को पूरा करेगा। ए 2 जमानत पर है। उसका जमानत बांड रद्द कर दिया जाता है। उसे उसके खिलाफ दी गई सजा को पूरा करने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।"

15. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, यहाँ इस न्यायालय के समक्ष दो अपीलों के साथ अपील की जाती है।

अपीलार्थियों के स्वयं के बारे में सुझाव

16. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री मनीषा भंडारी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को अपराध के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की, जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह तर्क दिया गया था कि मामला "कोई सबूत नहीं" में से एक है इसलिए 831

बालवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 832

जहाँ तक हत्या के आरोप का संबंध है। विद्वान वकील के अनुसार, पति घटना की तारीख से कुछ समय पहले दिल्ली में काम कर रहा था, जबकि मृतक अपने बेटे के साथ उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक शहर में रह रहा था। यह भी तर्क दिया गया कि मृतक की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि वह हृदय रोग से पीड़ित थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ डॉक्टर के मौखिक साक्ष्य से यह बताया गया कि मृतक का दिल बड़ गया था और दिल से संबंधित बीमारी अचानक मौत का कारण हो सकती है। वैकल्पिक में विद्वान वकील ने आत्महत्या के सिद्धांत को सामने रखा। आत्महत्या का यह सिद्धांत बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य के आधार पर सामने रखा गया था कि विसरा में "एल्यूमीनियम फॉस्फाइड" के रूप में जहर का पता चला था। यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि हो सकता है कि मृतक ने जहर खा लिया हो और उसने आत्महत्या कर ली हो क्योंकि वह अपनी बीमारी से थक गई थी।

17. यह भी तर्क दिया गया कि बचाव पक्ष के दो गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक को न तो पति द्वारा और न ही सास द्वारा किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि जैसे ही मृतक की मृत्यु हुई, पति ने तुरंत मृतक के परिवार के सदस्यों को उसकी आकस्मिक मृत्यु के बारे में सूचित किया। यह वही पति है जो शव को दिल्ली से उत्तराखंड स्थित अपने गांव ले गया था।

18. यह तर्क दिया गया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त होना चाहिए और न कि केवल दोषी हो सकता है।

19. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिन तथ्यों को अभियोजन पक्ष ने इस प्रकार स्थापित किया है, वे केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं होती हैं। परिस्थितियाँ साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर नहीं करती हैं।

20. अंत में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि को दरकिनार कर सकता है और इसे आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है। यह बताया गया कि दोषी-पति पिछले 9 साल से अधिक समय से सजा काट रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

21. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी दोनों अपीलों में योग्यता होने के कारण, उन्हें अनुमति दी जा सकती है।

राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

22. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जतिंदर कुमार भाटिया ने जोर देकर कहा कि अपीलार्थियों को संबंधित अपराधों के लिए दोषी ठहराने में उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा कानून की किसी भी त्रुटि के बारे में नहीं कहा जा सकता है।

23. यह जोरदार तर्क दिया गया कि मृतक अपने बेटे के साथ अपने गांव में रह रहा था जबकि पति दिल्ली में कोई नौकरी कर रहा था। मृतक के इलाज के बहाने पति उसे गाँव से दिल्ली ले आया और दिल्ली पहुंचने के तीन दिनों के भीतर ही यह घटना हो गई। यह तर्क दिया गया था कि अगर पति द्वारा सामने रखे गए मामले को स्वीकार किया जाना है तो यह माना जाना चाहिए कि मृतक के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन पति बहुत मौजूद था क्योंकि पति के अनुसार वह तुरंत मृतक को संजय गांधी अस्पताल ले गया था। अस्पताल में मृत घोषित किए जाने के बाद वह शव को गांव ले आया।

24. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 (संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम' या 'अधिनियम 1872') को देखते हुए, यह दोषी-पति को समझाना है कि वास्तव में क्या हुआ था। यह कहा जा सकता है कि दोषी-पति उन चीजों के बारे में विशेष जानकारी रखता है जो प्रासंगिक समय पर घटित हो सकती हैं।

25. यह तर्क दिया गया था कि विसरा में जहर की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि यह मृतक को किसी तरह से दिया गया था और पति के अलावा कोई भी जहर नहीं दे सकता था। यह भी तर्क दिया गया कि पति का अपराध करने का एक मजबूत मकसद था। पति को अपनी पत्नी को बहुत परेशान करने का भी दोषी ठहराया गया है और मृतक द्वारा अपने पिता को लिखे गए दो पत्रों से यह स्पष्ट है और साक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है।

833

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 834

26. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि दोनों अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से उन तथ्यों के बारे में पूरी तरह से मौन रखा है जिन्हें उनकी व्यक्तिगत जानकारी में कहा जा सकता है। जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उन्हें समझाने में विफलता दोषी-पति को अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

27. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं होने के कारण उन्हें खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

28. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

29. हम अभिलेख पर तथ्यों से उभरने वाली निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं:

ए। मौत का कारण जहर है। विसरा में पाया गया जहर एल्युमीनियम फॉस्फाइड था। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग खाद्यान्नों और पशुओं में कीटों और कृन्तकों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक के रूप में किया जाता है। दोषियों के लिए यह कहना बहुत अधिक है कि विसरा में एल्युमीनियम फॉस्फाइड की उपस्थिति उन दवाओं के कारण हो सकती है जो मृतक अपनी हृदय रोग के लिए लेती थी। उच्च खुराक में भी ऐसी दवाओं से शरीर में एल्युमीनियम फॉस्फाइड का निर्माण नहीं होगा। इस सिद्धांत को जो सामने रखा गया है, उसे बहुत बेतुका कहा जा सकता है। इस दिशा में कोई विशेष प्रश्न विशेषज्ञ गवाह (डॉक्टर) से नहीं पूछा गया है जब वह गवाह पेटी में था। ऐसी परिस्थितियों में, एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि एल्युमीनियम फॉस्फाइड या तो तरल रूप में या गोलियों के रूप में आरोपी पति द्वारा खरीदा गया था और वही मृतक को दिया गया था।

बी। हम अपीलार्थियों की ओर से सामने रखे जाने वाले आत्महत्या के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

ग. यदि यह दोषी-पति का मामला है कि वह मृतक को दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल ले गया था, तो उसे यह इंगित करने के लिए कुछ सबूत देने चाहिए थे कि उसे अस्पताल कैसे ले जाया गया, किस प्रकार के वाहन में और अस्पताल में मृतक की देखभाल कौन कर रहा था? मामले में

वर्तमान में, यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि यदि मृतक को अस्पताल ले जाया जाता और पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता, तो अस्पताल के अधिकारी दोषी-पति को अपनी पत्नी के शव को घर वापस ले जाने की अनुमति देते। यह एक चिकित्सकीय-कानूनी मामला बन जाएगा और अस्पताल पुलिस को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा।

घ. अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में परिवार के सदस्यों को सूचित नहीं करने का दोषी-पति का संदिग्ध आचरण। हालाँकि अपने आगे के बयान में, दोषी-पति ने कहा है कि उसने मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया था, फिर भी पीडब्लू 3 हरेंद्र सिंह (मृतक के चाचा) का सबूत कुछ और है। अपने मौखिक साक्ष्य में, उन्होंने निम्नानुसार बयान दिया है:

“मेरी भतीजी सुधा की मृत्यु 13.5.2007 पर हुई थी। इसकी जानकारी मुझे मेरे भाई शिवचरण ने टेलीफोन पर दी थी। शिवचरण दिल्ली में रह रहे थे। फिर मैंने शिवचरण से मामले की जांच करने को कहा। शिवचरण बलवीर के घर गया लेकिन वह वहाँ नहीं था। फिर मैंने यह जानकारी पुलिस स्टेशन, कोटद्वार में रात 2 बजे टेलीफोन पर दी और अपने भाई विरेंद्र को भी दी। इसके बाद, मेरा भाई सुबह कोटद्वार के पुलिस स्टेशन आया। मैं पुलिस स्टेशन भी गया। फिर मैं बलवीर गाँव गया था। वहाँ मैंने सुधा का शव देखा। मुझे नहीं पता कि सुधा की मृत्यु दिल्ली में हुई या गाँव में।”

30. उपरोक्त संदर्भ में, पीडब्लू 1 विरेंद्र सिंह (मृतक के पिता) का मौखिक साक्ष्य भी प्रासंगिक है। अपने मौखिक साक्ष्य में, पीडब्लू 1 ने निम्नानुसार कहा है:

“बलवीर सिंह वर्ष 2007 में मेरी बेटी को दिल्ली ले गए और अपने बेटे को यहाँ गाँव में ही छोड़ गए। जाने के समय, उसने मेरे भाई हरेंद्र को फोन किया, जो झंडी चौर में रहता है, और उससे कहा था कि वह दिल्ली नहीं जाना चाहती है। वह अनिच्छा से चली गई, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि वह कैसे चली गई थी।

दिल्ली जाने के दो दिन बाद, मेरे भाई को सूचना मिली कि सुधा की मृत्यु हो गई है। मेरे भाई शिवचरण ने इसकी जानकारी दी। बलवीर दिल्ली के मंगोलपुरी में रहता था। पड़ोसियों ने शिवचरण को बताया कि सुधा की मौत हो गई है। फिर, बलवीर सुधा के शव के साथ रतनपुर आया। फिर, मैं अगले दिन कोटद्वार आया और पुलिस स्टेशन में यह जानकारी दी। फिर पुलिस मेरे साथ 835 पर आई।

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 836

रतनपुर। वहाँ पुलिस ने जाँच रिपोर्ट तैयार की और मैं जाँच कार्यवाही में पंच था।

मेरी बेटी की गर्दन पर चोट के निशान थे। मुझे उसकी मौत पर संदेह था और इसलिए मैंने पोस्टमार्टम की मांग की। गवाह को जाँच रिपोर्ट पेपर नंबर 9 के दिखाया गया, जिस पर उसने पंचों की राय पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।”

31. अब हम मृतक द्वारा अपने पिता (पीडब्लू 1) को संबोधित दो पत्रों पर गौर करेंगे। इन दोनों पत्रों को पीडब्लू 1 के मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है और प्रदर्शित किया गया है। दिनांकित पत्र 20.05.2004, Exh। का-1 इस प्रकार पढ़ता है:

“तारीख: 20.05.04

आदरणीय माता और पिता, कृपया मेरा प्रणाम हाथ जोड़कर स्वीकार करें। इस समय मैं जीवित हूँ और आपके पूरे परिवार की भलाई के लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ। पिता साहब, यह पत्र लिखने का कारण यह है कि मैं यहां काफी परेशान महसूस कर रहा हूँ। जीवन में कोई विश्वास नहीं है कि यह कब समाप्त हो सकता है, मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पिता साहब, जब से मेरी शादी हुई है, मैं अपनी सास और पति के कृत्यों से बेहद परेशान महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक आपको यह नहीं बताया है कि यह सोचकर कि समय बीतने के साथ सद्बुद्धि प्रबल होगी, लेकिन ये दोनों मुझे खत्म करने का इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि आपके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप अपने पिता से 1 लाख रुपये नकद लाएंगे तो ही आप यहां रह सकते हैं, अन्यथा आप अपने माता-पिता के घर जाएंगे, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पिता एक मजदूर हैं और वह रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकते। 1 लाख। इस वजह से मेरी सास और पति मुझे पीट रहे हैं। उन्होंने मुझे कई हफ्तों तक खाना नहीं दिया। मैं भूखी और प्यासी रही और गाँव की महिलाओं ने किसी तरह इन लोगों से छिपकर मुझे खाना खिलाया। मेरी सास ने मुझे अपने 9 महीने के बेटे को दूध देने से भी मना कर दिया

और मुझे जंगल से लकड़ी लाने के लिए मजबूर किया।उसके बाद भी मुझे खाना नहीं दिया गया।मैं पूरे समय अपने वैवाहिक घर में रहा हूँ।आपने हमें कई बार विभिन्न समारोहों और समारोहों के लिए आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने न तो मुझे जाने दिया और न ही वे खुद गए।वे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

जाने के लिए फिर रु। एक लाख नहीं तो आपको यहां वापस नहीं आने दिया जाएगा।वे कहते हैं कि आपके माता-पिता और परिवार के सदस्यों को यहां नहीं आना चाहिए, अगर वे ऐसा करते हैं तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा।मेरे पिता, मुझे कोई सहारा नहीं है, मैं यहाँ भगवान की दया पर जी रहा हूँ। मैं यहाँ भूखी और प्यासी रह रही हूँ।उनके द्वारा की जा रही पिटाई के कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है।आज तक मैंने इन सभी तथ्यों को छुपाया है।मेरे पिता अगर आप रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं। एक लाख तो मेरी जान बचाई जा सकती है, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है।कृपया इस पत्र के बारे में किसी को न बताएं अन्यथा वे मुझे खत्म कर देंगे।तेरी बेटी।

गाँव मंगोलपुरी "

32. दूसरा अक्षर, एक्सएच। का-2 इस प्रकार पढ़ता है:

“आदरणीय माता और पिता, अपनी बेटी सुधा से प्रणाम हाथ जोड़कर स्वीकार करें।कृष्ण, मनोज, मुकेश को उनकी बहन से प्यार।मैं यहाँ ठीक हूँ और सर्वशक्तिमान के सामने आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ।मुझे अपना पिछला पत्र चाहिए जो मैंने आपको लिखा था।मैं किसी के दबाव में पत्र नहीं मांग रहा हूँ।मैं अपने घर में खुश हूँ।मैंने सुना है कि चाचा अनिल यहाँ आ रहे हैं और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वह पत्र उनके माध्यम से भेजें।मेरे पिता, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो कृपया अनिल अंकल के माध्यम से पत्र भेजें।मुझे यहाँ ही रहना है।मैं किसी के दबाव में यह नहीं मांग रहा हूँ, मुझे वह पत्र चाहिए। यदि आप वह पत्र अनिल अंकल के माध्यम से नहीं भेजते हैं तो मान लीजिए कि आपकी बेटी नहीं रही है।मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। अधिक मत सोचिए, केवल पत्र भेजें, मैं उसी का इंतजार करूंगा।आपके दामाद मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं।अगर वह मेरे साथ ठीक से व्यवहार करता है, तो सब कुछ ठीक है और आपको चिंतित नहीं होना चाहिए।आप बस चाचा के माध्यम से पत्र भेजें, क्योंकि मुझे उस पत्र की आवश्यकता है और उस पत्र को आपके पास रखने से कोई लाभ नहीं है।मैं यहाँ ठीक हूँ; आपको इसके बारे में खुश होना चाहिए।सो नू वास्तव में नहीं है।आपकी बेटी सुधा।”

साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** की प्रयोज्यता को लागू करने वाले कानून के सिद्धांत

33. साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** में कहा गया है:

837

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 838

“106. तथ्य को साबित करने का बोझ, विशेष रूप से ज्ञान के भीतर।— कब

कोई भी तथ्य विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है।

चित्रण

(क) जब कोई व्यक्ति किसी अन्य इरादे से कोई कार्य करता है, जो उस कार्य के चरित्र और परिस्थितियों से पता चलता है, तो उस इरादे को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।

(ख) क पर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करने का आरोप लगाया जाता है।यह साबित करने का भार कि उनके पास टिकट था, उन पर है।”

34. ऊपर निर्दिष्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** में यह प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।“विशेष रूप से” शब्द का अर्थ है ऐसे तथ्य जो मुख्य रूप से या असाधारण रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं।सामान्य नियम जो आपराधिक मुकदमों पर लागू होता है कि अभियुक्त के

अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है, किसी भी तरह से साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित तथ्यों के नियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अपवाद है। धारा 101 अपने चित्रण (ए) के साथ सामान्य नियम को निर्धारित करती है कि एक आपराधिक मामले में सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या किसी भी तरह से असमान रूप से कठिन होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं और जिन्हें वह बिना किसी बाधा या असुविधा के साबित कर सकता है।

35. शंभू नाथ मेहरा बनाम द स्टेट ऑफ अजमेर में सूचना दी गई है।

1956 एस. सी. 404, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति विवियन बोस के माध्यम से बोलते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रयुक्त "विशेष रूप से" शब्द पर विचार करते हुए कहा:

"11. ... "विशेष रूप से" शब्द इस पर जोर देता है। इसका अर्थ है ऐसे तथ्य जो उनके ज्ञान में पहले से या असाधारण रूप से हैं। यदि धारा की व्याख्या अन्यथा की जाती है, तो यह बहुत ही चौंका देने वाला निष्कर्ष होगा कि हत्या के मामले में यह साबित करने का बोझ आरोपी पर है कि उसने हत्या नहीं की क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने की या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

यह स्पष्ट है कि यह इरादा नहीं हो सकता है और प्रिवी काउंसिल ने दो बार इस धारा का अर्थ लगाने से इनकार कर दिया है, जैसा कि भारत के बाहर कुछ अन्य अधिनियमों में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह दिखाने का भार एक अभियुक्त व्यक्ति पर है कि उसने वह अपराध नहीं किया है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ये मामले एट्टीगाले बनाम द किंग, 1936 पी. सी. 169 (ए. आई. आर. वी. 23) (ए) और सेनेविरत्ने बनाम आर, 1936-3 सभी ई. आर. 36 हैं। 49 (बी)।"

36. शंभू नाथ (उपरोक्त) के उपरोक्त निर्णय को संदर्भित किया गया है।

(2021) 10 में रिपोर्ट किए गए नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य में

एस. सी. सी. 725, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

"22. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में हैं। जब अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो न्यायालय हमेशा एक उचित निष्कर्ष निकाल सकता है।

23. जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, यदि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर उस पर लगाए गए बोझ के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता परिस्थितियों की श्रृंखला के लिए एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा शासित मामले में, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित नहीं की जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत बोझ का निर्वहन करने में अभियुक्त की विफलता बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। जब कड़ी पूरी नहीं होती है, तो बचाव पक्ष का झूठ आरोपी को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है।"

(बल दिया गया)

37. तुलशीराम सहदु सूर्यवंशी और एक अन्य बनाम राज्य

महाराष्ट्र ने (2012) 10 एस. सी. सी. 373 में प्रतिवेदन दिया, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"23. यह स्थापित कानून है कि तथ्य का अनुमान साक्ष्य के कानून में एक नियम है कि अन्यथा संदिग्ध तथ्य का अनुमान कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से लगाया जा सकता है। जब साबित तथ्यों के अन्य समूह से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया

जाता है, तो अदालत तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। उपरोक्त स्थिति साक्ष्य अधिनियम, 839 की धारा 114 को ध्यान में रखते हुए मजबूत की गई है।

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 840

1872. यह अदालत को किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाने का अधिकार देता है जो उसे लगता है कि हुआ होगा। उस प्रक्रिया में, अदालतों को मामले के तथ्यों के अलावा प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना होगा। इन परिस्थितियों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित सिद्धांतों का भी उपयोग किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस धारा का उद्देश्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के बोझ को कम करना नहीं है, बल्कि यह उन मामलों में लागू होगा जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के बारे में अपनी विशेष जानकारी के आधार पर ऐसा कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके। स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. बनाम में निम्नलिखित अवलोकन को उद्धृत करना उपयोगी है। मीर मोहम्मद उमर [(2000) 8 एससीसी 382:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1516]: (एस. सी. सी. पी. 393, पैरा 38)

“38. न्यायाधीश विवियन बोस ने कहा था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए बनाई गई है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए कुछ तथ्यों को स्थापित करना असंभव होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं। शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404:1956 सी. आर. आई. एल. जे. 794] विद्वान न्यायाधीश ने कानूनी सिद्धांत को इस प्रकार कहा है: (ए. आई. आर. पी. 406, पैरा 11)

‘11. यह सामान्य नियम निर्धारित करता है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं और जिन्हें वह बिना किसी बाधा या असुविधा के साबित कर सकता है।

“विशेष रूप से” शब्द इस पर जोर देता है। इसका अर्थ है ऐसे तथ्य जो उनके ज्ञान में पहले से या असाधारण रूप से हैं।”

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

38. (2006) 10 एस. सी. सी. 681 में रिपोर्ट किए गए त्रिमुख मारौती किरकान बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, यह न्यायालय सदन में हत्या के समान मामले पर विचार कर रहा था। निम्नलिखित टिप्पणियों को वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक माना जाता है:

“14. यदि किसी घर की गोपनीयता के भीतर और ऐसी परिस्थितियों में जहां हमलावरों को अपनी पसंद के समय और परिस्थितियों में साजिश रचने और अपराध करने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करना बेहद कठिन होगा यदि अदालतों द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर देखा गया है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए। एक न्यायाधीश यह भी देखने के लिए अध्यक्षता करता है कि एक दोषी आदमी बच नहीं सके। दोनों सार्वजनिक कर्तव्य हैं। (स्टर्लैंड बनाम लोक अभियोजन निदेशक देखें [1944 ए. सी. 325:(1944) 2 सभी ई. आर. 13 (एच. एल.)-अरिजीत पसायत, जे. द्वारा पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह [(2003) 11 एस. सी. सी. 271:2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 135]। कानून अभियोजन पक्ष को ऐसे चरित्र के साक्ष्य का नेतृत्व करने का कर्तव्य नहीं देता है जिसका नेतृत्व करना लगभग असंभव है या किसी भी तरह से अत्यंत कठिन पंथ का नेतृत्व किया जाना है। अभियोजन का कर्तव्य ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करना है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया जाना संभव हो। यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसमें कहा गया है कि जब कोई

तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। इस खंड के साथ संलग्न चित्रण (बी) इस प्रावधान की सामग्री और दायरे पर कुछ प्रकाश डालता है और इसमें लिखा है:

“(ख) क पर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करने का आरोप लगाया जाता है। यह साबित करने का भार कि उनके पास टिकट था, उन पर है।”

15. जहां किसी घर के अंदर गुप्त रूप से हत्या जैसी घटना की जाती है, तो मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक बोझ निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप स्थापित करने के लिए उसके द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उतनी नहीं हो सकती जितनी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है। यह भार अपेक्षाकृत हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखते हुए घर के निवासियों पर इस बारे में एक ठोस स्पष्टीकरण देने का भार होगा कि अपराध कैसे किया गया था। द 841

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 842

घर के कैदी केवल चुप रहने और इस कथित आधार पर कोई स्पष्टीकरण न देने से बच नहीं सकते हैं कि अपने मामले को स्थापित करने का बोझ पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और किसी भी स्पष्टीकरण को देने का कोई कर्तव्य आरोपी पर नहीं है।

XXX

XXX

XXX

22. जहां किसी अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है और अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए प्रमुख साक्ष्य देने में सफल हो जाता है कि अपराध करने से कुछ समय पहले उन्हें एक साथ देखा गया था या अपराध उस आवास में होता है जहां पति भी सामान्य रूप से रहता था, तो यह लगातार माना जाता है कि यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि पत्नी को कैसे चोटें आईं या कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है जो गलत पाया जाता है, तो यह एक मजबूत परिस्थिति है जो इंगित करती है कि वह अपराध करने के लिए जिम्मेदार है।...”

(बल दिया गया)

39. सबूत के बोझ का सवाल, जहां कुछ तथ्य अभियुक्त की व्यक्तिगत जानकारी में हैं, इस मामले में इस अदालत द्वारा जांचा गया था

राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य ने (2000) 8 में रिपोर्ट किया

एससीसी 382। इस मामले में, हमलावरों ने मृतक को उस घर से जबर्न घसीटा जहां वह आरोपी के डर से शरण ले रहा था, और लगभग 2 बजे उसे ले गए: 30 रात में। अगले दिन सुबह उसका क्षत-विक्षत शव अस्पताल में पड़ा मिला। निचली अदालत ने अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ धारा 364 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की और राज्य ने भी हत्या के आरोप में अभियुक्तों को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए एक अपील का नेतृत्व किया। अभियुक्त ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था कि उनके द्वारा अपहरण किए जाने के बाद मृतक के साथ क्या हुआ था। सत्र न्यायाधीश ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कानून का उल्लेख करने के बाद कहा था कि मृतक को आखिरी बार आरोपी व्यक्तियों के साथ देखे जाने और अस्पताल में शव की खोज के बाद सबूतों की श्रृंखला में एक संबंध गायब था और यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के आरोप को किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा था। इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों पर ध्यान दिया और रिपोर्ट के पैरा 31 से 34 में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

“31. यह मूल नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है, को एक जीवाश्म सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जैसे कि यह बुद्धिमान तर्क की किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता है। अनुमान का सिद्धांत उपरोक्त नियम के लिए विदेशी नहीं है, न ही यह नियम के स्वभाव को प्रभावित करेगा। दूसरी ओर, यदि अभियोजन पक्ष के प्रमाण के बोझ से संबंधित पारंपरिक नियम को पांडित्यपूर्ण कवरेज में लपेटने की अनुमति दी जाती है, तो गंभीर रूप से अक्षम व्यक्ति प्रमुख लाभार्थी होंगे और समाज हताहत होगा।

32. इस मामले में, जब अभियोजन पक्ष पूर्व-वर्णित परिस्थितियों को स्थापित करने में सफल रहा, तो अदालत को कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमान कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक पाठ्यक्रम है जिस पर अदालत इस तरह की स्थितियों में भरोसा करती है।

33. तथ्य का अनुमान कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान है, जब तक कि इस तरह के अनुमान की सच्चाई को गलत नहीं माना जाता है। तथ्य का अनुमान साक्ष्य के कानून में एक नियम है कि अन्यथा संदिग्ध तथ्य का अनुमान कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से लगाया जा सकता है। जब साबित तथ्यों के अन्य समूह से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, तो अदालत तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। उपरोक्त सिद्धांत को भारत में विधायी मान्यता प्राप्त हुई है जब धारा 114 को साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया है। यह अदालत को किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाने का अधिकार देता है जो उसे लगता है कि हुआ होगा। उस प्रक्रिया में न्यायालय मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखेगा।

34. जब अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि महेश का अभियुक्त द्वारा अपहरण कर लिया गया था और वे उसे उस क्षेत्र से बाहर ले गए, तो केवल अभियुक्त को ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ जब तक कि वह उनके साथ नहीं था। यदि अपहरण के बाद थोड़े समय के भीतर उसकी हत्या पाई जाती है तो अनुमत तर्क प्रक्रिया अदालत को यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी कि अभियुक्तों ने उसकी हत्या की है। इस तरह के निष्कर्ष को बाधित किया जा सकता है अगर आरोपी अदालत को बताए कि महेश के साथ और क्या हुआ जब तक कि वह उनकी हिरासत में नहीं था।”

(बल दिया गया)

843

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 844

40. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत बरी होने के आदेश को उलट दिया, और अभियुक्तों को उक्त प्रावधान के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

41. इस प्रकार, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को आपराधिक मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी और सावधानी के साथ लागू करना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका आपराधिक मामलों में कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस देश में आपराधिक मुकदमों पर लागू होने वाला सामान्य नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों द्वारा किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया गया है।

42. धारा 106 को अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों का साक्ष्य पेश करने में अभियोजन पक्ष की अक्षमता को पूरा करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। इस धारा का उपयोग किसी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके दायित्व का निर्वहन नहीं करता है। यह अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है कि एक अपराध किया गया था, भले ही यह विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में एक मामला है और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का बोझ नहीं डालता है कि कोई अपराध नहीं किया गया था। ऐसे मामले में जहां अन्य परिस्थितियां स्वयं उसके स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उचित स्पष्टीकरण के अभाव में अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाना अभियोजन को उसके वैध बोझ से मुक्त करना है। इसलिए, जब तक इस तरह के साक्ष्य द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं जाती है। 43. धारा 106 स्पष्ट रूप से उन मामलों को संदर्भित करती है जहां अभियुक्त का अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर स्थापित किया जाता है जब तक कि अभियुक्त कुछ अन्य तथ्यों को विशेष रूप से अपनी जानकारी में साबित करने में सक्षम न हो जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निरर्थक बना देगा। यदि ऐसी स्थिति में, अभियुक्त कोई

स्पष्टीकरण देता है जो सिद्ध परिस्थितियों में यथोचित रूप से सत्य हो सकता है, तो अभियुक्त को उचित संदेह का लाभ मिलता है, हालांकि वह स्पष्टीकरण की सच्चाई को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे मामले में आरोपी कोई स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं देता है या गलत या अस्वीकार्य स्पष्टीकरण देता है, तो यह अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति है जो

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

हम उसके खिलाफ पैमाने को घुमा दें। प्रो. की भाषा मंग्लेनविल विलियम्स:

“साक्ष्य संबंधी बोझ को मामले के अंतिम चरण में स्थानांतरित करने से जूरी (न्यायालय) को अभियुक्त की खामोशी या उसके साक्ष्य से संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव को ध्यान में रखने की अनुमति मिलती है।”

44. पूर्वगामी को दोहराने के लिए विभिन्न नियमों में जो बात निहित है, वह यह है कि अभियोजन पक्ष के पास बचे हुए सभी मुद्दों को साबित करने के बजाय अपने मामले के सबूत के रूप में साक्ष्य का बोझ या साक्ष्य पेश करने का बोझ, यानी अभियोजन पक्ष के पास शेष सभी मुद्दों को साबित करने का बोझ और जो कभी नहीं बदलता है, यह विचार है कि अभियोजन पक्ष के लिए अपने हाथ से कुछ मुद्दों पर पूरी तरह से विश्वसनीय साक्ष्य देना असंभव है और इसलिए यदि वह भागने की इच्छा रखता है तो उन पर साक्ष्य देना अभियुक्त का काम है। अभियोजन पक्ष द्वारा हमेशा सकारात्मक तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए। लेकिन वही नियम हमेशा नकारात्मक तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है। यह अभियोजन पक्ष के लिए उन सभी संभावित बचाव या परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें समाप्त करने के लिए नहीं है जो किसी अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकते हैं। पुनः, जब कोई व्यक्ति अधिनियम के चरित्र और परिस्थितियों से पता चलता है कि उसके अलावा किसी अन्य इरादे से कार्य नहीं करता है, तो अन्य सभी संभावित इरादों को समाप्त करना अभियोजन पक्ष का काम नहीं है। यदि अभियुक्त का एक अलग उद्देश्य था जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में एक तथ्य है और जिसे उसे साबित करना चाहिए (प्रोफेसर ग्लैनविल विलियम्स-प्रूफ ऑफ गिल्ट, सीएच देखें। 7, पृष्ठ 127 और निम्नलिखित) और दिलचस्प चर्चा-पैरा 527 नकारात्मक अभिकथन और पैरा 528-पृष्ठ 438 और फॉइल पर, केनी की आपराधिक कानून की रूपरेखा, 17 वीं संस्करण की "एफ्री रेमेटिव काउंटर-एविडेंस की आवश्यकता है"। 1958 में। 45. लेकिन धारा 106 उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रश्रुत तथ्य न केवल अभियुक्त द्वारा बल्कि अन्य लोगों द्वारा भी ज्ञात होने में सक्षम है यदि वे उस समय मौजूद थे जब यह हुआ था। खंड में संलग्न चित्रों से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के चरित्र और परिस्थितियों से स्पष्ट नहीं होने वाले इरादे को विशेष रूप से उस व्यक्ति के ज्ञान के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए जिसका कार्य विचाराधीन है और यह तथ्य कि बिना टिकट के यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास बिना टिकट के पाए जाने से पहले एक स्तर पर टिकट था, विशेष रूप से यात्री की जानकारी में होना चाहिए: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, चित्रण (ए) और (बी) देखें।

845

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 846

46. सबूत के बोझ और सबूत के साथ आगे बढ़ने के बोझ के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है। आम तौर पर, किसी मुद्दे की नींव के रूप में स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक किसी भी संबंधात्मक प्रस्ताव पर सबूत का बोझ नहीं बदलता है, लेकिन गवाही के अनुसार सबूत का बोझ या स्पष्टीकरण का बोझ एक तरफ से दूसरे तरफ स्थानांतरित हो सकता है। इस प्रकार, यदि अभियोजन पक्ष के पास सबूत है जो यदि अदालत द्वारा विश्वास किया जाता है तो उन्हें उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध के बारे में आश्वस्त करेगा, तो आरोपी ऐसी स्थिति में है जहां उसे जवाबी सबूत के साथ आगे बढ़ना चाहिए यदि उसके पास ऐसा सबूत है। जब तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में होते हैं, तो ऐसे तथ्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उस पर होता है, चाहे वह प्रस्ताव सकारात्मक हो या नकारात्मक। उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया हो, क्योंकि अदालत को अभी भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वह दोषी ठहराए जाने से पहले एक उचित संदेह से परे दोषी है। तथापि, अभियुक्त द्वारा अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता को न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा इंगित निष्कर्ष को स्वीकार करने के रूप में या उन अनुमानों को स्वीकार करने के रूप में माना जा सकता है जिनका खंडन किया जा सकता है। यद्यपि कानूनी रूप से अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभियुक्त एक व्यावहारिक मामले के रूप में सबूत के साथ आगे बढ़ना आवश्यक हो सकता है। यह अभियोजन पक्ष पर निर्भर सबूत के बोझ को नहीं बदलता है (व्हार्टन का आपराधिक साक्ष्य, 12 वीं संस्करण। 1955, खंड। 1, च. 2 पी। 37 और पन्नी)। लेलेंड बनाम

राज्य ने 343 यू. एस. 790 = 96 एल. एड. में रिपोर्ट किया। 1302, राफ़ एल बनाम यू. एस. ने 271 यू. एस. में रिपोर्ट किया। 1054।

साक्ष्य अधिनियम की धारा **106** के पाठ में "प्राथमिक मामला" क्या है?

47. लैटिन अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टया का अर्थ है "पहली नज़र में", "पहली नज़र में", या "पहली छाप पर आधारित"। वेबस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी (1961 एडन.) के अनुसार, "प्रथम दृष्टया मामला" का अर्थ है "प्रथम दृष्टया साक्ष्य" द्वारा स्थापित एक मामला जिसका अर्थ है "तथ्य की धारणा को उठाने या प्रश्न में तथ्य को स्थापित करने के लिए कानून में पर्याप्त है जब तक कि इसका खंडन नहीं किया जाता है।" दीवानी और आपराधिक कानून दोनों में, इस शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि, प्रारंभिक जांच पर, एक कानूनी दावे में मुकदमे या निर्णय के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत होते हैं। अधिकांश कानूनी कार्यवाही में, एक पक्ष (आम तौर पर, वादी या अभियोजक) के पास सबूत का बोझ होता है, जिसके लिए उन्हें प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों के प्रत्येक तत्व के लिए प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यदि वे प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, या यदि कोई विरोध करता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

पक्ष विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत करता है, प्रारंभिक दावे को अन्य पक्षों द्वारा प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बिना खारिज किया जा सकता है।

48. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष को उन तथ्यों को साबित करने में सफल कहा जा सकता है जिनसे मृत्यु के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

49. तथ्य की धारणा कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक अनुमान है, जब तक कि इस तरह के अनुमान की सच्चाई को गलत नहीं माना जाता है।

50. यह समझाने के लिए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला क्या है, हमें मीर मोहम्मद (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना चाहिए, जिसमें इस न्यायालय ने क्रमशः पैरा 36 और 37 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"36. इस संदर्भ में हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित कानूनी सिद्धांत का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार है: "जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।"

37. इस धारा का उद्देश्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन के बोझ को कम करना नहीं है। लेकिन यह धारा उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि आरोपी ऐसे तथ्यों के बारे में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके।"

(जोर दिया गया) 51। हमें इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी गौर करना चाहिए

राम गुलाम चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य (2001)

8 एस. सी. सी. 311, जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 24 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"24. अन्यथा भी, हमारे विचार में, यह एक ऐसा मामला है जहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होगी। कृष्णानंद चौधरी पर बेरहमी से हमला किया गया और फिर छाती पर छुरा मारा गया। इस प्रकार बिजौय चौधरी के यह कहने के बाद कि "वह अभी भी जीवित है और उसे मार दिया जाना चाहिए", छुरा-ब्लो दिया गया। इसके बाद अपीलार्थी 847 ले गए।

शरीर को। इसके बाद कृष्णानंद चौधरी के साथ जो हुआ वह विशेष रूप से अपीलार्थियों की जानकारी में है। अपीलार्थियों ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि शव को ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया। कृष्णानंद चौधरी को तब से जीवित नहीं देखा गया है। स्पष्टीकरण के अभाव में, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी लड़के पर अपीलार्थी के परिवार के बच्चे का अपहरण और हत्या करने का संदेह कर रहे थे, यह अपीलार्थी को समझाना था कि उन्होंने उसे ले जाने के बाद उसके साथ क्या किया था। जब अपहरणकर्ताओं ने अदालत से उस जानकारी को रोक दिया, तो यह निष्कर्ष निकालने का पूरा औचित्य है कि उन्होंने लड़के की हत्या की थी। भले ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन के बोझ को कम करना न हो, लेकिन यह धारा वर्तमान जैसे मामलों में लागू होगी, जहां अभियोजन पक्ष तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिससे मृत्यु के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपीलार्थियों को अपने विशेष ज्ञान के आधार पर एक स्पष्टीकरण देना चाहिए जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए हम श्री मिश्रा के इस कथन में कोई सार नहीं देखते हैं।"

(जोर दिया गया) 52। हाथ में मामले में यह स्थापित किया गया है या अदालत की संतुष्टि के लिए साबित किया गया है कि मृतक अपने पति यानी अपीलार्थी-दोषी के साथ उस समय था जब उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो गई थी और इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में केवल अपीलार्थी-दोषी को ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ था जब तक कि वह उसके साथ नहीं थी।

सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने अगले बयान में किसी भी संभावित स्पष्टीकरण की पेशकश करने में अपील-संयोजक के हिस्से पर विफलता

53. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि अपीलार्थी-दोषी (पति) ने किसी भी तरह से यह नहीं बताया है कि वास्तव में उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था, विशेष रूप से जब यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी-दोषी अपनी पत्नी यानी मृतक के साथ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृतक की मृत्यु जहर के कारण हुई थी। विसरा में जो जहर पाया गया वह "एल्यूमीनियम फॉस्फाइड" पाया गया। हालाँकि, अपीलार्थी-दोषी ने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि जल्द ही मृतक बीमार पड़ गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

वह तुरंत उसे दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल ले गया, फिर भी, इस संबंध में नाम के लायक कोई सबूत नहीं है। अपीलार्थी-दोषी से कुछ सबूत देने की उम्मीद थी कि संजय गांधी अस्पताल में क्या हुआ था। उन्होंने पूरी तरह से मौन रखा है। यह केवल अपीलार्थी-दोषी ही बता सकता था कि वह किन परिस्थितियों में और किस तरीके से अपनी पत्नी को संजय गांधी अस्पताल ले गया था और जिसने अस्पताल में अपनी पत्नी की देखभाल की थी। यदि यह उसका मामला है, कि अस्पताल में लाए जाने पर उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया था, तो यह मानना मुश्किल है कि अस्पताल के अधिकारियों ने अपीलकर्ता को कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना शव को घर वापस ले जाने की अनुमति दी थी।

54. उपरोक्त संदर्भ में, हमें इस निर्णय पर विचार करना चाहिए।

देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य के मामले में न्यायालय ने रिपोर्ट दी

ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 801 उक्त निर्णय में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद है जिसमें विद्वान न्यायाधीश परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष में उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में अभियुक्त की विफलता के प्रभाव से निपटते हैं। पुनरावृत्ति की कीमत पर, कानून बहुत स्पष्ट है कि अभियुक्त किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बाध्य नहीं है, कि ऐसा करने के लिए उस पर कोई बोझ नहीं डाला गया है और सबूत की जिम्मेदारी आपराधिक मुकदमे के किसी भी चरण में अपराध के महत्वपूर्ण मामले के संबंध में नहीं बदलती है। लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है:

"यह सच है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में न केवल साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित की जानी चाहिए, बल्कि पूरी की गई श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त के निर्दोष होने की उचित संभावना को खारिज किया जा सके। लेकिन ऐसे मामले में जहां विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां आरोपी को संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं, उचित अवज्ञा के साथ और समय और स्थिति के संबंध में मृतक की निकटता में, और वह

कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, जो यदि स्वीकार किया जाता है, हालांकि साबित नहीं होता है, तो पूरे मामले पर उसकी बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए एक उचित आधार प्रदान करेगा, इस तरह के स्पष्टीकरण या गलत स्पष्टीकरण का अभाव स्वयं एक अतिरिक्त लिंक होगा जो श्रृंखला को पूरा करता है।"

(जोर दिया गया) 55। हमारे विचार में, उपरोक्त परिच्छेद वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर बहुत बलपूर्वक लागू होता है।

849

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 850

56. यहां तक कि जहां विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में ऐसे तथ्य हैं, जो उसके अपराध या निर्दोषता पर प्रकाश डाल सकते हैं, जहां भी मामला हो, अभियुक्त उन पर आरोप लगाने या उन्हें साबित करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह धारा स्वतः आपराधिक विचारणों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो विधानमंडल निश्चित रूप से ऐसा अधिनियमित करता। हम मानते हैं कि सही नियम यह है कि धारा 106 आपराधिक मुकदमे में किसी अभियुक्त पर कोई बोझ नहीं डालती है, लेकिन यह कि, जहां अभियुक्त उन तथ्यों पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में होने चाहिए, और जो उसकी बेगुनाही के साथ संगत परिकल्पना के किसी भी सिद्धांत का समर्थन कर सकता है, अदालत देवनंदन मिश्रा (उपरोक्त) में मार्ग के सिद्धांत के अनुरूप कोई स्पष्टीकरण देने में उसकी विफलता पर भी विचार कर सकती है, जिसे हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। 1918 ए. आई. आर. मैड में रिपोर्ट किए गए स्मिथ बनाम आर. में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में मामले को इस रूप में रखा गया है। 111, अर्थात्, यदि अभियुक्त अपने अपराध के एकमात्र वैकल्पिक सिद्धांत की व्याख्या करने की स्थिति में है, तो स्पष्टीकरण के अभाव को ध्यान में रखा जा सकता है। वर्तमान मामले में, सिद्ध तथ्यों को एक साथ लेते हुए, हम किसी भी वैकल्पिक सिद्धांत के बारे में अटकलें लगाने में भी असमर्थ हैं जो आरोपी की बेगुनाही के साथ संगत है।

57. उपरोक्त संदर्भ में, हम किसी निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं।

कालू उर्फ लक्ष्मीनारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य में इस न्यायालय का

(2019) 10 एस. सी. सी. 211 में प्रतिवेदित, जिसमें इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता पर अपने विभिन्न अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार अवलोकन किया:

"16. हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है, अपीलार्थी की ओर से उद्धृत उदाहरणों को वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक नहीं माना जाता है। एक बार जब अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित कर लिया, तो अपीलकर्ता उन परिस्थितियों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य था, जिनके तहत मृतक की घर के अंदर अप्राकृतिक मौत हुई थी। इसलिए किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देने में उनकी विफलता इस निष्कर्ष पर कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि वे मृतक के हमलावर थे।"

(जोर दिया गया) 58। हमें (1974) 4 एस. सी. सी. 193 में रिपोर्ट किए गए सावल दास बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी विचार करना चाहिए। उक्त में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

मामले में निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि, ऊपर सूचीबद्ध स्थापित परिस्थितियों पर, अदालत के लिए कोई अन्य निष्कर्ष खुला नहीं छोड़ा गया था, सिवाय इसके कि अपीलार्थी और उसके पिता और सौतेली माँ ने मृतक श्रीमती की हत्या को संयुक्त रूप से किया था। आई. डी. 1 की सुबह चंदा देवी ने कहा कि अपीलार्थी और उसके पिता ने गलती को छिपाने के लिए शव का जल्दबाजी में और चुपके से निपटान कर दिया था। इसने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा था कि अपीलार्थी ने अपने लिखित बयान में एक असफल याचिका दायर की थी कि, श्रीमती. चंदा देवी, जिन पर उनके द्वारा नायलॉन की साड़ी पहनने का आरोप लगाया गया था, के बारे में कहा जाता है कि जब वह अपने कमरे में मिट्टी के तेल के चूल्हे का उपयोग कर रही थीं, तो दुर्घटनावश उन्हें गोली लग गई, जिससे उनके शरीर पर व्यापक जलने से उनकी मृत्यु हो गई और वे गिर गईं। अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि श्रीमती. चंदा देवी बार-बार गर्भधारण के कारण कमजोर हो गई थीं और उनका स्वास्थ्य

खराब था और उन्हें अस्थमा, कमजोर हृदय और पेट की शिकायतों से भी दम घुट रहा था। उसने छह बच्चों को जन्म दिया था।
59. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“8. हम सोचते हैं कि इस दलील को साबित करने का भार श्रीमती. चंदा देवी की मृत्यु उसी तरीके से हुई जिस तरह से अपीलार्थी ने अपीलार्थी पर आरोप लगाया था। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 और 106 के प्रावधानों से स्पष्ट है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने ठीक ही कहा था कि अपीलकर्ता किसी भी तथ्य या परिस्थितियों का विश्वसनीय या ठोस सबूत देने में बुरी तरह विफल रहा है जो उन याचिकाओं का समर्थन कर सकते हैं जो श्रीमती. चंदा देवी की मृत्यु हो गई क्योंकि उनकी नायलॉन साड़ी गलती से मिट्टी के तेल के चूल्हे से गिर गई थी। ट्रायल कोर्ट ने ठीक ही कहा था कि केवल यह तथ्य कि कुछ गवाहों ने कमरे से कुछ धुआं निकलते देखा था, पास में एक रसोईघर के साथ जब भोजन पकने की संभावना थी, यह संकेत नहीं दे सकता कि श्रीमती. चंदा देवी की साड़ी को खूब पसंद किया गया था। न तो हत्या की गई महिला, न ही अपीलकर्ता और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य को इधर-उधर भागते हुए दिखाया गया और न ही उनके खिलाफ मदद की गुहार लगाई गई।

9. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को अभियोजन पक्ष द्वारा सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि वह धारा केवल वहीं लागू होती है जहां अपराध के वास्तविक कृत्य से संबंधित तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान के भीतर होता है, जैसे कि वे परिस्थितियाँ जिनमें या वह इरादा जिसके साथ किसी अभियुक्त ने कोई विशेष कार्य किया था जो कथित रूप से अपराध का गठन करता है। धारा 851 की भाषा

बालवीर सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 852

106 साक्ष्य अधिनियम, हमारी राय में, इस पर इस तरह के संकीर्ण निर्माण का समर्थन नहीं करता है। इस न्यायालय ने गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 460:(1956) सी. आर. आई. एल. जे. 827] कि एक अभियुक्त द्वारा विशेष रूप से स्थापित याचिका को साबित करने का बोझ, जो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर सकता है, निश्चित रूप से उस पर निर्भर करता है। यह एक अलग बात है कि सबूत की मात्रा जिसके द्वारा वह एक उचित विश्वास पैदा करने के अपने बोझ का निर्वहन करने में सफल हो सकता है, कि परिस्थिति, जो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त कर सकती है, अभियोजन पक्ष पर किसी अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के बोझ से कम है।

10. हालाँकि, न तो धारा 103 का आवेदन और न ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का आवेदन, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अभियोजन मामले को साबित करने के अपने सामान्य या प्राथमिक बोझ का निर्वहन करने के कर्तव्य से मुक्त कर सकता है। यह केवल तभी होता है जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करता है, जो यदि विश्वास किया जाता है, तो एक दोषसिद्धि को बनाए रखेगा, या जो एक प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, तो सवाल उन तथ्यों पर विचार करने के लिए उत्पन्न होता है जिनके सबूत का भार आरोपी पर हो सकता है। हमारे सामने मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न है: क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने प्रारंभिक या सामान्य और प्राथमिक बोझ का निर्वहन किया है?”

(बल दिया गया)

60. हम भी वही सवाल उठाते हैं जो ऊपर उल्लिखित सवाल दास (उपरोक्त) में पूछा गया था, “क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने प्रारंभिक या सामान्य और प्राथमिक बोझ को पूरा किया है?”

61. हमारा विचार है कि इस निर्णय के पैरा 28 में हमारे द्वारा वर्णित परिस्थितियाँ एक प्रथम दृष्टया मामले से अधिक हैं जो अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने और आरोपी पति पर यह समझाने का बोझ डालने में सक्षम बनाती हैं कि वास्तव में उसकी पत्नी की मृत्यु की तारीख को क्या हुआ था।

62. ये अपीलें हमें याद दिलाती हैं कि इस अदालत ने मामले में क्या टिप्पणी की थी

धरम दास वाधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: “लाभ का नियम टी

उचित संदेह का मतलब यह नहीं है कि एक कमजोर विलो हिचकिचाहट के हर झोंके के लिए झुकता है। न्यायाधीश कठोर सामग्री से बने होते हैं और उन्हें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

साक्ष्य, परिस्थितिजन्य या प्रत्यक्ष से होने वाले वैध निष्कर्ष।"

ऐसी परिस्थितियों में अदालतों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है और यह उम्मीद की जाती है कि अदालतें ऐसे मामलों से अधिक यथार्थवादी तरीके से निपटेंगी और प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं, निष्पक्ष जांच या साक्ष्य में मामूली खामियों के कारण अपराधियों को भागने की अनुमति नहीं देंगी क्योंकि अन्यथा अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अपराध के पीड़ितों को अपराध के बिना सजा दिए जाने से पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है।

63. परिणामस्वरूप, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती हैं। 64. हालाँकि, 2014 की आपराधिक अपील संख्या 2430 की अपीलकर्ता माहेश्वरी देवी (सास) को केवल आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, इसलिए हम उनकी सजा को पहले की अवधि तक कम कर देते हैं। अन्यथा भी वह जमानत पर है। माहेश्वरी देवी को अब आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जमानत बांड जारी किए जाते हैं।

65. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान